एमएनएस और शिवसेना की फ़ासीवादी राजनीति

महाराष्ट्र में गैरमराठियों के खिलाफ़ शिवसेना और शिवसेना से ही निकली राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ज़हर उगलना बंद नहीं किया है। गत वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 'महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए' नाम पर जो हंगामा मचाया था, वह लोग़ों ने भूला नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिहार और उत्तर प्रदेशवासियों के खिलाफ़ हिंसात्मक व्यवहार पर उतर आई थी जिसके परिणामस्वरूप लाखों की संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग़ों को अपनी रोजी-रोटी छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। महाराष्ट्र शिवसेना का आतंक इतना ज्यादा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा था। उन दिनों मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य औद्योगिक इलाकों से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में लोग़ जानवरों की तरह ठुंसकर भागने को मजबूर हो गए थे।

राज ठाकरे और उनके संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस रवैये की देश भर में व्यापक आलोचना हुई। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ठाकरे की आलोचना की, पर महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार कानों में तेल डाले चुपचाप देखती रही। जब सभी दलों यहां तक कि 'साम्प्रदायिक' भाजपा ने भी ठाकरे की गतिविधियों की आलोचन शुरू कर दी, क्योंकि ऐसा न करने पर हिंदी भाषी राज्यों में उसका जनाधार खिसक सकता था। परिस्थिति की भयावहता को देखकर सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को दिल्ली तलब किया और ठाकरे को नियंत्रित करने का फ़रमान जारी रखा।

इधर पूरे देश में ठाकरे की गिरफ़्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी। केन्द्र के काफ़ी दबाव के बाद राज ठाकरे की 'प्रतीकात्मक' गिरफ़्तारी हुई, पर गिरफ़्तारी के दूसरे दिन से ही उसे आजाद छुट्टा छोड़ दिया गया और ठाकरे अपने 'किले' से घृणा का ज़हर फैलाता रहा।

मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। उद्योग-धंधों और व्यवसाय-वाणिज्य का वह देश का बड़ा केन्द्र है। लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश से गए लोग वहां उद्योग का पहिया घुमाते हैं। उनके नौकरी छोड़कर भाग जाने का मतलब था-उद्योगपतियों का नुकसान। उस समय प्रमुख उद्योगपतियों ने यह कहा भी कि हिंदीभाषी राज्यों से आए लोग मेहनती तो होते ही हैं, तकनीकी रूप से भी दक्ष हैं जबकि स्थानीय लोग़ इन मामलों में इनसे पीछे तो हैं ही, बराबर वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं और काम करने के बजाय धरना-प्रदर्शन में ज़्यादा ही मशगूल रहते हैं। उनका मानना था कि बिहार और उत्तरप्रदेशवासियों के पलायन से उन्हें काफी नुकसान हुआ है और विदेशों से आए ऑर्डर को पूरा कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।

पर ठाकरों को इसकी क्या परवाह! उन्होंने तो 'चौथ-वसूली' से इतना ज्यादा धन एकत्रित कर लिया है कि उनकी सात पीढ़ियां सिर्फ़ हरामखोरी करके खा सकती हैं और अय्याशी कर सकती हैं। आज पूरे शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत 'चौथ-वसूली' ही है। इस परिवार के मुंबई के प्रमुख माफ़िया होने के कारण सभी इनसे ख़ौफ़ खाते रहे हैं। बड़े से बड़े अधिकारी इनके आगे सिर झुकाते हैं और सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी इनके आगे साष्टांग दंडवत करते हैं।

वैसे देखा जाए तो शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की विचारधारा और कार्यशैली एक है। ये एक माफ़िया की तरह फ़रमान जारी करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने फ़रमान जारी किया कि मुंबई में रहने वाले तमाम गैर मराठी लोगों को मराठी भाषा सीखनी पड़ेगी। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों ने उत्तर भारतीय हिंदी भाषी टैक्सी चालकों एवं अन्य लोगों को मराठी सीखने के लिए किताबें बांटनी शुरू कर दीं। लेकिन राज ठाकरे ने अपने गुंडों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गैर मराठियों को मराठी भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से भगाने की जरूरत है।

इन्होंने कुछ वैसा ही अभियान शुरू किया है जो दशकों पहले शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने गुजरातियों के साथ किया था। पर गुजराती व्यावसायिक गतिविधियों में इस कदर लगे हुए थे कि उन्हें पूर्णत: वहां से भगा पाना शिवसेना के लिए संभव नहीं हो सका। इसी प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई और महाराष्ट्र के उद्योगों की रीढ़ बन चुके हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कहने पर उद्योगों और छोटे-बड़े व्यवसायों का संचालन करने वाले लोग़ इन्हें हटाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बरसाती मेंढकों की तरह लाख टरटराते रहें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रांतीयतावाद और भाषावाद के आधार पर गैर मराठियों को राज्य से नहीं भगा सकते। हां, इस तरह ज़हर उगलने से इनका वोट बैंक जरूर सिकुड़ सकता है जिसे बढ़ाने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। इनका मराठा मानुष और मराठावाद चलने वाला नहीं है। इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि यह शिवाजी का ज़माना नहीं है। जिस समय शिवाजी ने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ़ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा था, वह सामंती ज़माना था, पर आज हम राष्ट्रवाद के युग में जी रहे हैं जिसमें दुनिया के लगभग सारे देश अंतरराष्ट्रीयताबाद के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े हैं।

पर राज ठाकरे और उनके भ्राता शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे संभवत: इस बात को नहीं समझ रहे हैं और मुंबई के साथ-साथ पूरे महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझ रहे हैं। उनका यह भ्रम तब दूर हो जाएगा जब महाराष्ट्र में अगले चुनाव होंगे। राज ठाकरे मतदाताओं को रिझाने के लिए यह भी कह रहे हैं कि राज्य में नौकरी सिर्फ़ उन्हें ही देनी चाहिए जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं। क्या मतदाता इतने बेवकूफ हैं कि इस तरह के बहकावों में आ जाएं। चाहे अखिल भारतीय सेवाएं हों या राज्य सरकारों की सेवाएं, कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह किसी भी राज्य का हो, नौकरी के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने और नौकरी हासिल करने का पात्र है। उसे यह अधिकार देश के संविधान ने प्रदान किया है। देश की नीतियां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे गुंडों के सरदारों के कहने से नहीं बनाई जातीं। महाराष्ट्र अपेक्षाकृत देश का एक समृद्ध राज्य है। पर उसी महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में न जाने कितने किसानों ने खेती में लगातार घाटा होने और कर्ज के मकड़जाल में फंस जाने के कारण आत्महत्याएं कीं। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो मराठा मानुष की बात करते हैं, कभी भी उनके बारे में सोचा? उनके प्रति संवेदना दिखाई? उनकी यह स्थिति तो हिंदी भाषी राज्यों से जाने वाले मेहनतकश किसानों के कारण नहीं हुई। यह स्थिति तो महाराष्ट्र सरकार की ग़लत किसान विरोधी नीतियों के कारण हुई। फ़िर इस मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की? क्यों करेंगे? लोग भूख से अथवा कर्ज के जाल में फंस कर मरते हों, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है।

वे तो अय्याशी भरा जीवन जीते हैं, पार्टियों का आयोजन करते हैं जिसमें मुंबई के बड़े-बड़े अफ़सरान शिरकत करते हैं, यहां तक कि पुलिस के उच्चाधिकारी भी। एक माफ़िया सरदार द्वारा आयोजित पार्टियों में जब राजनीति और प्रशासन के बड़े-बड़े ताकतवर लोग़ शिरकत करते हों तो इसी से समझा जा सकता है कि इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे।

शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में स्वभाविक एकजुटता है, क्योंकि दोनों हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करती हैं। पर भाजपा और शिवसेना में एक विरोधाभास भी है। वह यह कि शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना को जहां राज्य की राजनीति तक सीमित रहना है, भाजपा को अखिल भारतीय राजनीति करनी है। उसमें भी भाजपा का आधार उत्तर भारत के हिंदीभाषी राज्यों में ही है। अगर भाजपा, मनसे अथवा शिवसेना की हिमायत करती है तो उसे हिंदीभाषी राज्यों के वोट बैंक से हाथ धोना पड़ेगा। यही कारण है कि पहले भी नरम लहजे में ही सही भाजपा ने मनसे की गतिविधियों का विरोध किया था, पर अब पानी सिर से ऊपर गुज़रने लगा है तो भाजपा द्वारा इनके विरोध का स्वर भी कड़ा हुआ है।

इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना का विरोध किया है जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि संघ को उन्हें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। संघ के साथ ही भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों के लोग़ों को पूरे भारत में कहीं भी जाने, बसने, नौकरी अथवा व्यवसाय करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी भाषायी, धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान में विश्वास नहीं करती है जो लोग़ों में भेदभाव करे। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनकी पार्टी धारा-370 का बराबर विरोध करती है। कुल मिलाकर अपनी नई नीति के तहत संघ ने मनसे और शिवसेना का जबरदस्त विरोध किया है ताकि भाजपा को आने वाले दिनों में परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा अलग है और भाषा का अलग।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के अधिकांश बड़े नेता हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही हैं और उनके वोटर भी। इसलिए ऐसी संभावना बनती है कि भाजपा और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ें। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि उद्धव ठाकरे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें दक्षिण के राज्यों में लोग़ों को हिंदी सिखानी चाहिए। इधर मोहन भागवत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए यह कह दिया कि मनसे और शिवसेना यदि उत्तर भारतीयों पर हमलावर होती है तो संघ उनकी रक्षा में उतरेगा। भाजपा ने भी उत्तर भारतीय लोगों की रक्षा में उतरने की घोषणा की है। भाजपा और संघ की यह समझ है कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों का पक्ष लेने से उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा होगा। इधर मनसे और शिवसेना भाषा और मराठी अस्मिता के सवाल को उठाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती हैं।

एक सवाल यह है कि मुंबई सिर्फ़ मराठी भाषियों के लिए ही है तो बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने ही परिवार की स्मिता ठाकरे को हिंदी फ़िल्में बनाने से क्यों नहीं रोकते? साथ ही उन्हें मुंबई में रहकर हिंदी फ़िल्में बनाने वाले निर्माता-निर्देशकों, अभिनेता-अभिनेत्रियों को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते और सिर्फ़ मराठी फ़िल्में बनाने को क्यों नहीं कहते? साथ ही, वे उन बड़े औद्योगिक घरानों को जिनकी भाषा मराठी नहीं है, मुंबई अथवा महाराष्ट्र छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते?

साथ ही वे उन स्कूलों, कॉलेजों को बंद क्यों नहीं कराते जो मराठी नहीं, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देते हैं और जिनमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बच्चे पढ़ते हैं।

क्या उनमें है इतनी ताकत? नहीं। वे सिर्फ़ किसी तरह रोज़ी-रोटी चलाने वाले मज़दूरों और टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो अगर एक दिन की भी हड़ताल कर दें तो पूरी मुंबई ठप हो जाएगी। इसलिए मनसे और शिवसेना को चाहिए कि वह वोटों के चक्कर में घृणा की राजनीति करना छोड़ें। पर यह कहना वैसा ही है जैसे भेड़िए से यह उम्मीद करना कि वह शाकाहारी हो जाएगा।

बहरहाल, केन्द्र सरकार को इस सवाल पर सोचना होगा और विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन नागों को नाथना होगा। सोनिया को यह भी समझना होगा कि केन्द्र सरकार में शरद पवार जैसे शिवसेना के पिट्ठू भी बैठे हैं जो हर वक्त प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहते हैं।

- मनोज कुमार झा

क्या ठाकरे महाराष्ट्र के मूल निवासी है?

आज राज ठाकरे यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गैर मराठी लोगों को नौकरियां नहीं देनी चाहिए। क्या ठाकरे को यह पता है कि उनके पूर्वज मुंबई कहां से आए थे?

अगर पता नहीं हो तो उनके बारे में बाल ठाकरे से पूछना चाहिए। बाल ठाकरे के दादा मध्यप्रदेश के खंडवा से आए थे और स्वयं बाल ठाकरे को हाईस्कूल की शिक्षा दिलाने खंडवा भेजा गया था। फ़िर ठाकरे कैसे मराठा-मानुष हैं?

शिक्षा में मराठी माध्यम?

बीएमसी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से जहां मराठी भाषा शिक्षा का माध्यम है, 27 प्रतिशत बच्चे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में चले गए हैं। ऐसा इसलिए कि मराठी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में कैरियर नहीं बन सकता। बढ़िया कैरियर तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हासिल करने पर ही मिल सकता है।

एक बात और सिर्फ़ मराठी जानने वाला व्यक्ति सिर्फ़ मराठी ज्ञान के आधार पर पूरे देश में आसानी से नहीं घूम सकता। उसे पग-पग पर भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना कराना पड़ेगा। लेकिन हिंदी का कामचलाऊ ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आसानी से पूरे देश में घूम सकता है और भाषा संबंधी कठिनाइयां शायद ही उसे झेलनी पड़े।

वेलेंटाइन डे पतनशील पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण

वेलेंटाइन डे आया और चला गया। वैसे अब औपचारिक रूप से भी वेलेंटाइन डे एक दिन का नहीं रहा, बलिक सप्ताह भर चलने वाला आयोजन बन गया है। इससे युवाओं की मौज-मस्ती में काफी वृद्धि हुई है। युवा तो यही चाहेंगे कि वेलेंटाइन डे सप्ताह भर न चलकर महीने भर चल जाए ताकि उनके मौज-मजे लगातार महीने भर तक चलें। वैसे तो उच्च वर्गीय युवकों के लिए वर्ष के 365 दिन ही वेलेंटाइन डे हैं। कभी उनकी मौज-मस्ती में कमी नहीं आती। जब वेलेंटाइन डे सिर्फ़ एक दिन का हुआ करता था तो भी युवा इसे लेकर कम रोमांचित नहीं हुआ करते थे। यह डे सिर्फ़ बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित था। पर अब तो छोटे कस्बों और गांवों में भी इसकी धमक सुनाई पड़ रही है। मीडिया और बाज़ार ने इसे हर जगह पहुंचा दिया है। अब युवा बेधड़क होकर 'हग डे' मनाते हैं यानी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से लिपटते-चिपटते हैं। खुले में लिपटने-चिपटने में इन्हें शर्म भी नहीं आती। शर्म क्यों आए? 'हग डे' तो वेलेंटाइन डे का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा वेलेंटाइन डे के अंतर्गत 'किस डे' का भी प्रावधान किया गया है। इस दिन युवा-युवतियां बेधड़क होकर एक दूसरे को चूमते-चाटते हैं, वह भी खुले में। निस्संदेह वेलेंटाइन डे का यह सबसे आकर्षक पहलू है। 'रोज डे' और 'गिफ्ट डे' में वह मज़ा कहां कि जो 'हग डे' और 'किस डे' में होता है। कुछ लोग जो भगवाधारी हैं, वेलेंटाइन डे के विरोधी हैं, पर आमतौर पर लोग इसके समर्थक हैं, या उन्हें इसके समर्थन और विरोध से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ ऐसे ही लोग हैं, जो सिर्फ़ तमाशबीन हैं। विरोधी लट्ठ लेकर वेलेंटाइन डे मनाने वालों के पीछे पड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पार्कों, मॉल्स आदि पर पुलिस बल तैनात रहता है। इस तरह सरकार प्रेमी जोड़ों को खुले में प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करे तो वेलेंटाइन डे के विरोधी लाठियों से उन्हें चूर डालें। वेलेंटाइन डे के ये विरोधी भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं और वेलेंटाइन डे मनाने वाले पश्चिमी संस्कृति के जहां खुलेआम प्रेम के नाम पर चूमाचाटी करने की पूरी छूट है। वेलेंटाइन डे मनाने का विरोध करने वालों को सिर्फ़ भारतीय संस्कृति का पक्षधर ही नहीं, बल्कि सांप्रदायिक और रूढ़िवादी तक कहा जाता है। सवाल है, किस किताब में यह लिखा है कि खुलेआम नग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन करने वालों को आधुनिक और इसका विरोध करने वालों को पिछड़ा व साम्प्रदायिक कहा जाए। सच पूछा जाए तो वेलेंटाइन डे को समर्थन देने वालों में बाज़ार सबसे आगे है। मॉल संस्कृति ने इसे और भी बढ़ावा दिया है। वेलेंटाइन डे से सबसे अधिक फायदा बाज़ार को है। सूचना क्रांति ने भी इसे बढ़ावा देने का काम किया है। रह गया इस डे के समर्थन और विरोध का तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति वेलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता, नग्नता और उच्छृंखला का समर्थन नहीं करेगा।

- मनोज